

माननीय मुख्य मंत्री , उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 14-11-2015 को पूर्वान्ह 11.00

बजे 5 कालीदास मार्ग, लखनऊ में फिफथएस्टेट द्वारा आयोजित "मंच 2015 सोशल एंटरप्राइज सम्मिट" का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थित अधिकारीगण एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों की सूची संलग्न है।

श्री वेंकटेश रामाकृष्ण, सीनियर एसोसियेट एडिटर, फ्रंट लाइन मैगजीन एवं एडवोकेट एडवाइजर एण्ड मैन्टोज, फिफथ स्टेट ने उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, सदस्य राज्य योजना आयोग श्री सुधीर पन्वार, मैनेजिंग ट्रस्टी फिफथएस्टेट सुश्री पल्लवी गुप्ता, प्रमुख सचिव, आयुक्त, जिलाधिकारियों के साथ वहाँ उपस्थित विभिन्न सामाजिक उद्यमियों एवं उद्योग जगत से आये लोगो का स्वागत किया।

सुश्री पल्लवी गुप्ता ने अन्य प्रदेशों से आये सामाजिक उद्यमियों का अभिनन्दन करते हुए कहा कि समाजिक समस्या का हल समाज के अंगो के एक साथ आये बगैर नहीं हो सकता। सरकार, सामाजिक उद्यमी एवं कारपोरेट जगत फिफथएस्टेट के प्रमुख अंग है। इन तीनों को संगठित करने के उद्देश्य से फिफथएस्टेट ट्रस्ट ने मंच नामक कार्यक्रम की स्थापना की है। मंच की शुरुवात 4 फरवरी 2014 में प्रदेश सरकार से सरकारी तंत्र का सहयोग, सामाजिक क्षेत्र के इनोवेटिव सल्यूशन और कारपोरेट सेक्टर की आर्थिक सहायता के बल पर किसी भी प्रोजेक्ट का विस्तार करने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा किया गया था।

मंच 2014 के दो लाभार्थी श्री ब्योमकेश मिश्रा मेघा लर्निंग फाउण्डेशन के सहसंस्थापक एवं श्री प्रतीक ईकोजेन सलुसन के संस्थापक ने अपने गत वर्ष के अनुभव को सभी सम्मानित सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया। दोनों ने ही मंच के प्रयासों की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की इस प्रकार के प्रयास निरन्तर सरकार की तरफ से होते रहने चाहिए। श्री ब्योमकेश ने तत्कालीन प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा एवं प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा (सुश्री कल्पना अवरथी), जिलाधिकारी, गोरखपुर (श्री रंजन कुमार) एवं बाराबंकी के जिलाधिकारी द्वारा उनकी सहायता के लिए धन्यवाद दिया। श्री प्रतीक ने कानपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी श्रीमती रोशन जैकब को आभार व्यक्त करते हुए तथा उनके द्वारा सी०एस०आर० सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता शासन स्तर पर विभिन् विभागो के आधिकारियों के साथ विचार विमर्श के उपरान्त चयनित सात सामाजिक उद्यमियों द्वारा प्रस्तुतिकरण किया गया जिसके माध्यम से प्रदेश में विभिन्न समस्याओं के समाधान करने पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये।

'वाटर लाईफ' के श्री सुदेश मेनन ने ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने में प्रतिबद्धता को दोहराया एवं सरकार द्वारा वाटर लाईफ को दी जाने वाली सुविधा जिसमें 10x10 मी० की जगह, बिजली का कनेक्शन एवं पानी का श्रोत उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के संबंध में आशा व्यक्त की कि उपस्थित कारपोरेट जगत प्लांट को स्थापित करने में और प्रशासन उन्हें सी०एस०आर० फंड दिलाने में सहयोग करेगा।

'अरविन्द आई केयर' के मो० गौथ ने अपने विजन सेन्टर को CSC एवं PHC में बनाये जाने एवं प्रदेश नोडल अफसर को नामित करने का आश्वासन मिलने पर एवं इसके अतिरिक्त नेशनल हेल्थ स्कीम और अपने विजन सेन्टर को जिला अस्पताल से जोड़ने एवं पूर्ण सहयोग मिलने के आश्वासन पर प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया।

'मेरा गाँव पावर' के श्री संदीप पाण्डे ने सरकार से उन जगहों को चिन्हित करने में सहयोग देने की बात कही जहाँ पर सौर्य ऊर्जा की अत्यन्त आवश्यकता है एवं CSR के माध्यम से निजी कंपनी द्वारा कुछ गाँवों को गोद लेने अपेक्षा की गयी है।

अपने प्रस्तुतिकरण में SMV व्हीलस' के श्री नवीन कृष्णा ने सरकार द्वारा उन्हें मिले आश्वासन को बताते हुए कहा उन्हें लोगल परमिट के साथ-साथ व्यवसायिक सहयोग के लिए बैंक से ऋण लेने में मदद का आश्वासन भी दिया गया है। प्रशासन द्वारा लोगों को ट्रेनिंग देने में भी सहयोग दिया जायेगा।

'आगा खॉ फाउण्डेशन' के श्री जुल्फीकर खान ने स्टेट रूरल लाइव्लिहुड मिशन में अपनी भागीदारी के आश्वासन को बताते हुए उन्होंने SHG की संख्या को बढ़ाने का आश्वासन दिया। सी०एस०आर० के सहयोग द्वारा गाँवों को गोद लेने की कामना की है।

'बेसिसिक्स कन्सल्टेन्सी एण्ड टेक्नालजी सर्विसेस लिमिटेड' की श्रीमती गौरी कृष्णा ने बताया कि सरकार उनके FPO माडल को कैपसिटी बिल्डिंग एवं ट्रेनिंग में सहयोग देगी। सरकार द्वारा स्थापित FPO को जिला स्तर पर सहयोग दिलाते हुए इनपुट और आउटपुट के लिए आवश्यक सभी प्रकार के लाइसेन्स दिलाने में भी सहयोग प्रदान करेगी।

फयूल के केतन देश पाण्डे ने अपने उद्यम को सरकार द्वारा दिये जा रहे सहयोग के बारे में बताया सरकार उनके स्कूलों को अप्रोच करने में मदद करेगी और सी एस आर द्वारा जिला एवं ग्रामीण स्तर पर भी सहायता मिलने की इच्छा व्यक्त की है।

इन सात उद्यमियों के प्रस्तुतिकरण के उपरान्त सुश्री पल्लवी गुप्ता ने अपने संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण के द्वारा समस्त उपस्थित व्यक्तियों को सूचित किया कि फिफथएस्टेट द्वारा वर्ष 2015-16 के लिये चयनीत अन्य परियोजनाए को सरकार की तरफ से सहयोग के लिए आमंत्रित किया गया है।

श्री सुधीर पंवार ने उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए बताया की पूरे भारत वर्ष में सर्वप्रथम यह प्रयास उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जोकि सराहनीय है। उन्होंने आशा व्यक्त कि इस प्रयास को सरकारी तंत्र का पूर्ण सहयोग इसी प्रकार मिलता रहेगा व इससे प्रदेश का विकास तीव्र गति से होगा।

मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ने मा० मुख्यमंत्रीजी को अवगत कराया की उन्होंने अपने सभी उच्च अधिकारियों के साथ दिनांक 9 नवम्बर 2015 को अपने सभाकक्ष में हुयी बैठक में सभी परियोजना पर विचार करते हुए इनका चयन किया था। ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य की योजनाओ का अत्यंत गरीब एवं लाभार्थी तक न पहुँच पाने पर चिंता व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त कि इन सामाजिक उद्यमियों के माध्यम से इसे सम्भव बनाया जा सकेगा। सभी को आश्वासन करते हुए उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में इन परियोजना को माडल के रूप में विकसित करते हुए उसके उपरान्त सम्पूर्ण प्रदेश में इसका क्रियान्वन किया जायेगा। उन्होंने मा० मुख्यमंत्रीजी को बताया कि फिफथएस्टेट ने जिलों में जाकर सम्बन्धित जिलाधिकारियों से उनके जिले की समस्याओं पर विचार विमर्श करने के उपरांत इन परियोजनाओं का चयन किया है। मुख्य सचिव ने माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वासित किया कि यहाँ उपस्थित अधिकारियों द्वारा ही नहीं अपितु प्रदेश के समस्त अधिकारीगण से इन परियोजना को सम्पूर्ण सहयोग मिलेगा। उन्होने यह भी बताया कि CSR का सम्पूर्ण मेकॅन्सिज्म बना लिया गया है जिसमें उद्योग बन्धु को नोडल ऐजेन्सी बनाया है जिनके माध्यम से इन प्रोजेक्ट को आर्थिक सहायता दी जायेगी।

मा० मुख्यमंत्रीजी ने अपने संबोधन में फिफथएस्टेट की सरहाना करते हुए आश्वासन दिया कि सरकार का उन्हें पूर्ण सहायता एवं सहयोग मिलेगा। मुख्य सचिव को निर्देशित किया कि वह एक व्यक्ति को नामित करे जो उत्तर प्रदेश में चल रहे सामाजिक कार्यों का निरीक्षण करते हुए सीधे सामाजिक उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करे ताकि किसी अधिकारी के स्थानान्तरण एवं प्रमोशन के कारण इन प्रयासों की गति में फर्क न पड़े। उन्होंने अपने संबोधन में पर्यावरण की रक्षा एवं बेरोजगारी की समस्या का तत्वरित गति से निवारण करने को कहा। सामाजिक उद्यमियों को इन्वोवेशन फंड से सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने समस्त उद्योग

जगत से आग्रह किया कि वे अपने CSR फंड को राज्य की ज्वलंत समस्याओं के समाधान में लगाये। इसी को आगे बढ़ाते हुए मा० मुख्यमंत्री जी ने उद्योग बन्धुओं को निर्देशित किया कि वे इन सामाजिक उद्यमियों की सहायता करें और देखे की प्रोजेक्ट सुचारु रूप से क्रियान्वित हो सके। फिफथएस्टेट एवं सुश्री पल्लवी गुप्ता के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने सभी उपस्थित प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि फिफथएस्टेट द्वारा चयनित प्रोजेक्टस को सम्पूर्ण सहयोग दे और प्रयास करें कि अगले साल तक सारे प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से संचालित हो जाये।

सुश्री पल्लवी ने अपने प्रस्तुतिकरण एक सारणी के माध्यम से निम्न परियोजनाओं को विभिन्न जनपदों के सहयोग हेतु प्रस्तुत किया जिसके संबंध में निम्न निर्णय लिए गए।

स्वास्थ्य

1. अरविन्द आई केयर— कार्यवाही: जिलाधिकारी— आगरा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, गोरखपुर एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. करुणा ट्रस्ट— कार्यवाही: जिलाधिकारी— आगरा अलीगढ़, कानपुर, गोरखपुर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. आपरेशन आशा— कार्यवाही: जिलाधिकारी— आगरा, गोरखपुर एवं संबंधित विभाग।
4. बेधी हेल्थ— कार्यवाही: जिलाधिकारी— गौतम बुद्ध नगर, इलाहाबाद एवं संबंधित विभाग।
5. वर्ल्ड हेल्थ पाटनर्स— कार्यवाही: जिलाधिकारी—नेरठ, गोरखपुर एवं संबंधित विभाग।

क्लीन एनर्जी

6. सिम्या एनर्जी इंडिया— कार्यवाही: जिलाधिकारी—मुरादाबाद, अलीगढ़, बाराबंकी, नेरठ, कानपुर एवं संबंधित विभाग।
7. हस्क पावर सिस्टम—कार्यवाही: जिलाधिकारी—बाराबंकी, इलाहाबाद तथा NEDA।
8. मेरा गाँव पावर— कार्यवाही: जिलाधिकारी— श्यामली, बाराबंकी, कानपुर इलाहाबाद तथा NEDA।

स्वच्छ जेयजल

9. वटर लाइफ इंडिया- कार्यवाही: जिलाधिकारी-आगरा, श्यामली, मेरठ, गारेखपुर एवं ग्राम्य विकास विभाग।

शिक्षा

10. मैजिक बस इण्डिया फाउन्डेशन- कार्यवाही: जिलाधिकारी- आगरा, श्यामली, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ तथा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग।
11. एक्सपैरिफन एजुकेशनल सल्यूशन- कार्यवाही: जिलाधिकारी-गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर तथा बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग।
12. फ्यूल- कार्यवाही: जिलाधिकारी- हापुर, बाराबंकी, गौतमबुद्ध नगर, कानपुर, गोरखपुर एवं संबंधित विभाग।

लेबर एवं स्किल

13. अजीविका ब्यूरो एवं निर्वाण- कार्यवाही: जिलाधिकारी-हापुर, लखनऊ, अलीगढ़, श्यामली, श्रम विभाग एवं संबंधित विभाग।
14. अनन्त लर्निंग- कार्यवाही: जिलाधिकारी- आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, इलाहाबाद एवं संबंधित विभाग।

रोजगार एवं आजीविका

15. SMV व्हील्स- कार्यवाही: जिलाधिकारी- आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, इलाहाबाद एवं संबंधित विभाग।
16. श्री कामधेनु इलेक्ट्रानिक्स- कार्यवाही: जिलाधिकारी- लखनऊ, मेरठ एवं संबंधित विभाग।
17. गोट ट्रस्ट- कार्यवाही: जिलाधिकारी- अलीगढ़, गोरखपुर एवं संबंधित विभाग।
18. बेसिसिक्स बेबल- कार्यवाही: जिलाधिकारी- गोरखपुर, कानपुर एवं संबंधित विभाग।
19. B2R टेक्नालीज- कार्यवाही: जिलाधिकारी- आगरा, गोरखपुर एवं संबंधित विभाग।

महिला सशक्तिकरण

20. जन सहास सोशल डेवलपमेन्ट— कार्यवाही: जिलाधिकारी—कानपुर, गोरखपुर एवं संबंधित विभाग।
21. आगा खॉ फाउन्डेशन— कार्यवाही: जिलाधिकारी— मुरादाबाद, बाराबंकी, कानपुर, गोरखपुर, SLRM एवं संबंधित विभाग।

कृषि

22. बेसिसिक्स (एफ.पी.ओ.)— कार्यवाही: जिलाधिकारी— आगरा, गोरखपुर, कृषि विभाग एवं संबंधित विभाग।
23. एग्रिवोल्यूशन — कार्यवाही: जिलाधिकारी— आगरा, लखनऊ, हापुर, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर, गोरखपुर, श्यामली, कृषि विभाग।

अन्य

24. रिन्धु आई.टी.— कार्यवाही: जिलाधिकारी— आगरा, झाँसी, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, हापुर, अलीगढ़, गोरखपुर एवं संबंधित विभाग।
25. श्रमिक भारती— कार्यवाही: जिलाधिकारी— आगरा, हापुर, बाराबंकी, गोरखपुर एवं संबंधित विभाग।
26. अभिटेक— कार्यवाही: जिलाधिकारी— लखनऊ, गोरखपुर एवं संबंधित विभाग।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

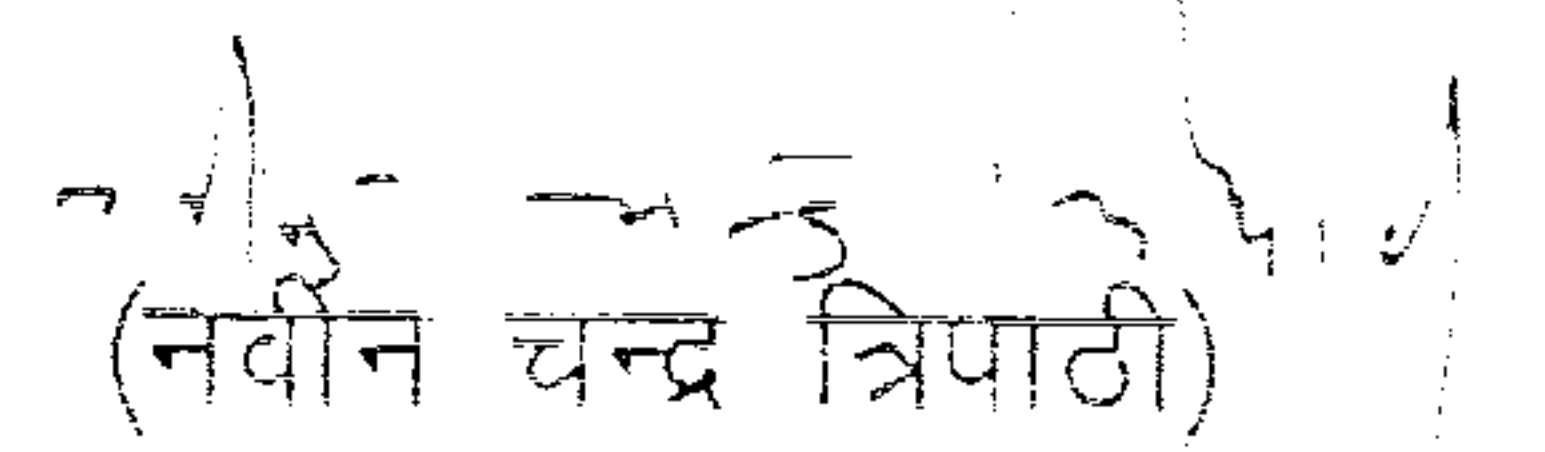
नियोजन अनुभाग-1

संख्या-¹²⁵⁸ /35-1-2015-6/8(2)/2015

लखनऊ : दिनांक: ०5 जनवरी, 2016

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्रीजी, उ०प्र० सरकार।
 - 2- प्रमुख स्टाफ आफीसर / निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
 - 3- श्री सुधीर पन्वार, मा० सदस्य, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग, लखनऊ
 - 4- प्रमुख सचिव / सचिव-
पंचायती राज / श्रम / परिवहन / ऊर्जा / आई०टी०एंड एलेक्ट्रॉनिक्स / ग्राम्य विकास /
नहिला कल्याण / चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण / कृषि / कृषि शिक्षा / कृषि
अनुसंधान / बेसिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा / उच्च शिक्षा / नेडा / वोकेशनल एजुकेशन एंड
स्किल डेवेलपमेंट / आवास / नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 5- निजी सचिव, प्रमुख सचिव / विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।
 - 6- मण्डलायुक्त-आगरा / इलाहाबाद / आजमगढ़ / लखनऊ / चित्रकूट / गोरखपुर /
मेरठ / मुरादाबाद / सहारनपुर।
 - 7- जिलाधिकारी-आगरा / लखनऊ / गौतमबुद्धनगर / कानपुर / गोरखपुर / श्यामली /
बाराबंकी।
 - 8- निदेशक- नेडा / नेशनल हेल्थ मिशन।
 - 9- निदेशक, दीर्घकालीन एवं राज्य इन्वोल्वेशन सेल, नियोजन विभाग।
 - 10- श्रीमती पल्लवी गुप्ता, प्रबन्ध निदेशक, फिफ्थ इस्टेट को इस आशय से प्रेषित कि
उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी उद्यमियों / संस्थाओं को कार्यवृत्त की प्रति
अपने स्तर से अग्रतर कार्यवाही हेतु भेजने का कष्ट करें।
 - 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)

विशेष सचिव।